होम लोन सस्ते, फिर भी मकानों की बिक्री घटी

साल 2025 में मकानों की बिक्री एक प्रतिशत घटकर 3 .48 लाख रह गयी

नई दिल्ली, 07 जनवरी. कीमतों में भारी उछाल के कारण देश के आठ बड़े शहरों में साल 2025 में मकानों की बिक्री एक प्रतिशत घटकर 3.48 लाख रह गयी. रियल एस्टेट सलाह कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि होम लोन पर ब्याज की दरों में नरमी के बावजूद यह गिरावट देखी गयी है. यह रिपोर्ट प्राथमिक आवास बाजार के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गयी है.

रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट कंपनियों ने बताया कि होम लोन पर ब्याज दरों में कमी, मजबूत आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति में कमी के कारण

पिछले साल मकानों की बिक्री में गिरावट पर लगाम रही. आठ बड़े शहरों में शामिल मुंबई महानगरीय क्षेत्र में मकानों की बिक्री पिछले साल एक प्रतिशत बढ़कर 97,188 इकाई पर पहुंच गयी. वहीं औसत कीमत सात प्रतिशत बढ़कर 8,856 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गयी.

बेंगलुरु में 55,373 इकाई की के साथ बिक्री लगभग स्थिर रही और औसमत कीमत 12 प्रतिशत बढ़कर 7,388 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गयी.

पुणे में बिक्री तीन प्रतिशत घटकर 50,881 इकाई रही जबकि कीमत पांच प्रतिशत बढ़कर 5,016 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गयी.

> दिल्ली-एनसीआर में बिक्री में नौ प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखी गयी. यहां पिछले साल 52,452 मकान बिके. दूसरी तरफ, औसत कीमत 19 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि के साथ 6,028 प्रति वर्ग फुट पर रही. हैदराबाद में बिक्री चार प्रतिशत बढ़कर 38,403 इकाई पर और कीमत 13 फीसदी बढ़कर 6,721 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गयी. अहमदाबाद में घरों की बिक्री दो प्रतिशत बढ़कर 18,752 इकाई पर रही और औसत कीमत तीन प्रतिशत बढ़कर 3,197 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गयी. चेन्नई में बिक्री में सबसे अधिक 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 18,262 मकान बिके.

गिरावट से उबरा रुपया

मुंबई, 07 जनवरी. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 12 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.18 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा में लगातार चार दिन की गिरावट के बाद तेजी लौटी है. पिछले कारोबारी दिवस पर सोमवार को यह 9.50 पैसे टूटकर 90.30 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपये में आज शुरू से ही तेजी रही. यह आठ पैसे की बढ़त में 90.22 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. इसका दिवस का निचला स्तर 90.25 रुपये और ऊपरी स्तर 90.08 रुपये प्रति डॉलर रहा. बैंकों की डॉलर बिकवाली से आज रुपये में मजबूती रही. हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की तेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रुपये पर दबाव पड़ा और इसकी बढ़त सीमित रही.

एमपी-सीजी में ज्यादा मोबाइल ग्राहक जियो के पास

जियो ने 2 .3 लाख नए मोबाइल और 65 हजार ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े

भोपाल 07 जनवरी. मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल में रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े है. टेलीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की नवंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर से जियो ने मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहकों को जोड़ा है.

नवंबर 2025 में रिलायंस जियो से 2.3 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े है. वहीं, जियो फाइबर और एफडब्लूए और यूबीआर जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को 65 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने अपनाया है. जबकि समान अवधि में एयरटेल के 97 हजार और बीएसएनएल के 13

हजार मोबाइल ग्राहक बढ़े लेकिन सबसे ज्यादा वाडाफोन-आईडिया के 1 लाख से ज्यादा मोबाइल ग्राहक कम हुए है. ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ में सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. वहीं,फिक्सड वायरलेस एक्सेस और वायरलाइन ब्राडबैंड उपभोक्ता 29.7 लाख से ज्यादा है. इसमें जियो के मोबाइल ग्राहक 4.7 करोड़ और ब्रॉडबैंड ग्राहक संख्या 15 लाख से कहीं अधिक है. साथ ही मार्केट शेयर पर गौर करें तो मोबाइल उपभोक्ता में बाजार हिस्सेदारी 60.6 फिसदी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाता में मार्केट शेयर 59.6 प्रतिशत है. साल 2025 भारत के डिजिटल सफर में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हुआ.

अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत का निर्यात मजबूत

दिसंबर 2025 में भी बढ़ा भारत का निर्यात : पीयूष गोयल

अमेरिका की टैरिफ नीति बेअसर, भारत के निर्यात आंकड़े सकारात्मक

नई दिल्ली, 07 जनवरी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के निर्यात कारोबार में वृद्धि बनी हुई है और दिसंबर 2025 के निर्यात की रिपोर्ट के भी आंकड़े सकारात्मक हैं.

पीयूष गोयल ने यहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन के बाद मीडिया से अलग से बातचीत में अमेरिका में भारत के खिलाफ ऊंचे आयात शुल्क से तिरुपुर (तमिलनाडु) जैसे कपड़ा और परिधान उद्योग संकुलों पर बुरे प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, यदि अमेरिकी बाजार प्रभावित हुआ भी है तो हमने जो नये समझौते किये है और हमें जो नये बाजार मिले हैं उससे हमें नये अवसर मिले हैं. वाणिज्य मंत्री ने कहा, मेरे पास दिसंबर के निर्यात की रिपोर्ट आ गयी है. यह जनवरी

के मध्य में जारी होगी लेकिन मैं कह सकता हूं कि दिसंबर 2025 के निर्यात के आंकड़ों में वृद्धि बनी हुई है. उन्होंने कहा, तिरुपुर जैसे कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए जाने वाले औद्योगिक इलाकों से जो जानकारी मिली है, इससे लगता है कि अमेरिकी शुल्कों का प्रभाव यदि है भी तो सीमित है.

हमने जो समझौते किये है जो नये अवसर तलाशे गये हैं उससे निर्यात मजबूत बना हुआ है. उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने गत अगस्त में भारत पर पहले 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, उसके बाद उसने रूस से कच्चे तेल के आयात के लिए दड़ात्मक शुल्क के रूप में 25 प्रतिशत शुल्क और लगा कर इसे 50 प्रतशत कर दिया.

> केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार से दो दिवसीय महत्वपूर्ण आधिकारिक वार्ता के लिए ब्रुसेल्स जा रहे हैं जिसमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया जा सकता है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस यात्रा के दौरान, श्री गोयल यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविच के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करेंगे ताकि व्यापार वार्ता टीमों का रणनीतिक मार्गदर्शन दर्शन कर लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सके.

अमेजन पे ने भारत में सावधि जमा की शुरुआत की

नई दिल्ली, 07 जनवरी। भुगतान सुविधा प्लेटफॉर्म अमेजन पे ने भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए मंगलवार को सावधि जमा सुविधा की शुरुआत की घोषणा की। अमेजन पे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने इसके लिए दो प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस तथा पांच बैंकों शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ग्राहक अमेजन पे पर सिर्फ 1,000 रुपये से सावधि जमा खाता खोल सकते हैं।

चांदी में गिरावट, सोना हुआ कमजोर

4,161 रुपए नीचे आई चांदी

नई दिल्ली, 07 जनवरी. बुलियन बाजार में बुधवार को जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला. चांदी ने वायदा कारोबार में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 2.59 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर छू लिया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते कीमतों में तेज गिरावट आ गई. सोने की कीमतों में भी सीमित दायरे में दबाव देखा गया.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति और अहम आर्थिक आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क नजर आए. बुलियन बाजार में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव दर्ज किया

गया. चांदी की कीमतों ने जहां वायदा बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण कीमतें तेजी से फिसल गईं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी शुरुआती कारोबार में 2,59,692 रुपये प्रति किलोग्राम के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में 4,161 रुपये या 1.61 प्रतिशत टूटकर 2,54,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई.

इससे एक दिन पहले मंगलवार को चांदी में जोरदार तेजी देखी गई थी, जब कीमत 13,167 रुपये या 5.35 प्रतिशत उछलकर 2,59,322 रुपये तक पहुंच गई थी. लगातार चार सत्रों की तेजी के बाद आई इस गिरावट को विशेषज्ञ ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली का नतीजा मान रहे हैं. चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी दबाव देखने को मिला. एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 633 रुपये या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,38,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में भी यही रुझान रहा. सोना भी 21 डॉलर गिरकर 4,475.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा.

वित्त मंत्रालय ने पेश की 3 साल की पीपीपी मेगा पाइपलाइन

नई दिल्ली, 07 जनवरी. देश में बुनियादी ढांचे के विकास को नई रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 852 परियोजनाओं की तीन साल की पाइपलाइन जारी की है.

17 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इन परियोजनाओं का मकसद निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और केंद्र व राज्यों के सहयोग से सड़कों, ऊर्जा, रेल और अन्य क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है.

झदेश में अवसंरचना विकास को गति देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने 17 लाख करोड़

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
सत्यमेव जयते

रुपये से अधिक की लागत वाली 852 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का तीन साल का रोडमैप जारी किया है. यह योजना केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं के अनुरूप तैयार की गई है और इसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2026 से शुरू होगा. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा तैयार इस पाइपलाइन में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ-साथ 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.

दिग्गज कंपनियों में बिकवाली से लुढ़के प्रमुख सूचकांक

मुंबई, 07 जनवरी. विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को दिग्गज कंपनियों में बिकवाली देखी गयी और प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुए।

बीएसई का सेंसेक्स 102.20 अंक (0.12 प्रतिशत) टूटकर 84,961.14 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 37.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत उतरकर 26,140.75 अंक पर रहा। दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया। मंगलवार को 85,063.34 अंक पर बंद होने वाला सेंसेक्स करीब 443 अंक की गिरावट में खुला। यह नीचे 84,617.49 अंक और ऊपर 85,075.99 अंक तक गया। निफ्टी-50 का दिन का निचला स्तर 26,067.90 अंक और अधिकतम स्तर 26,187.15 अंक रहा। प्रमुख सूचकांकों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने पैसा लगाया।

चावल, दालों के भाव बढ़े खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 07 जनवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ दालों में भी तेजी रही जबकि गेहूं और चीनी में टिकाव रहा. खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 19 रुपये बढ़कर 3,866 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 2,849 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रहा. आटा पांच रुपये सस्ता हुआ. दाल-दलहनों में तेजी रही. उड़द दाल औसतन 31 रुपये और मूंग दाल 30 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

भविष्योन्मुखी विकास के लिए सस्ती बिजली जरूरी

भारत के विकास की कुंजी सस्ती और सुरक्षित बिजली : अनिल अग्रवाल

नई दिल्ली, 07 जनवरी. देश के भविष्योन्मुखी विकास के लिए ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करते हुए वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि विकास के लिए सस्ती बिजली जरूरी है.

विजुअल कैपिटलिस्ट का एक ग्राफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, भारत के पास बिजली (पारंपरिक और नवीकरणीय) उत्पादन और पारेषण में बड़ा अवसर है. हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए, फैक्ट्रियों के लिए और डाटा सेंटरों के लिए सस्ती बिजली आपूर्ति करनी है. उन्होंने परियोजनाओं में तेजी लाने और नीति को सरल बनाने की वकालत करते हुए लिखा कि बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण एक ही नीति का हिस्सा होने चाहिये. कंपनियों को हर पहलू पर काम करना चाहिये.

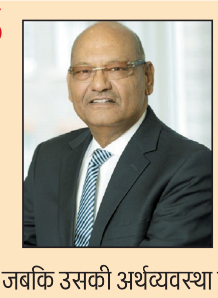

> अग्रवाल ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और महत्वपूर्ण खनिजों से संचालित भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में सस्ती और सुरक्षित बिजली की भूमिका बेहद अहम होगी. ग्राफ के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि आज चीन की बिजली उत्पादन क्षमता अमेरिका की तुलना में लगभग दोगुनी है, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था का आकार अमेरिका से काफी छोटा है.

समाचार विशेष

पद की मर्यादा पहले ! नितिन अब 'माननीय'

भाजपा ने मिलने वालों के लिए तय किया नया प्रोटोकॉल

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे में हालिया बदलावों ने पार्टी के भीतर एक नई कार्यशैली और कड़े अनुशासन का संदेश किया है. जहां राष्ट्रीय स्तर पर पद की गरिमा बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में गुटबाजी और जातिगत राजनीति करने वालों को कड़ा आईना दिखाया गया है.

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के मनोनयन के बाद पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन में व्यक्ति से ऊपर पद होता है. चूंकि नबीन उम्र और अनुभव में कई वरिष्ठ नेताओं से छोटे हैं, इसलिए अक्सर आपसी चर्चाओं में वरिष्ठ नेता उन्हें नाम से संबोधित कर देते थे. इसे देखते हुए पार्टी ने सभी नेताओं और पदाधिकारियों को सख्त

हिदायत दी है कि बातचीत के दौरान 'प्रोटोकॉल' का पूरा ध्यान रखा जाए.

निजी संबंध जैसे भी, पद की गरिमा जरूरी- निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि पुराने निजी संबंध चाहे जो भी रहे हों, लेकिन आधिकारिक चर्चा के दौरान पद की गरिमा के अनुरूप ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए. यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नितिन नबीन के जल्द ही पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना है.

> **प्रोटोकॉल की चर्चा जोरों पर**
>
> लोगों की मानें तो इस कड़े रुख से उन लोगों के पसीने छूट रहे हैं जो अब तक गुट बनाकर और जातिगत राजनीति के सहारे अपनी जड़ें जमाए हुए थे. ऐसे नेताओं को डर है कि यदि उनकी पिछली 'कारगुजारियां' नए अध्यक्ष तक पहुंच गईं, तो उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट आ सकता है. पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग इस अनुशासन की सराहना कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि आगामी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाना बेहद जरूरी था. वर्तमान में, भाजपा मुख्यालय से लेकर जिलों तक में इस 'नए अनुशासन' और प्रोटोकॉल की चर्चा जोरों पर है.

यूपी, तमिलनाडु में कांग्रेस के इरादे

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी के नेता अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं. वे राज्यों में अपने सहयोगी दलों को परेशान कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और राहुल गांधी व अखिलेश यादव की तुलना करते हुए राहुल को बड़ा और महान नेता बताया.

इसके बाद एक दूसरे सांसद राकेश राठौड़ आए, जिन्होंने कहा कि सपा को यूपी में लोकसभा की जो 37 सीटें मिली हैं और वह कांग्रेस के कारण मिली हैं. उनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हालात बदले और उसका लाभ सपा को मिला.

राठौड़ के मुताबिक सपा के नेता उनसे बातचीत में कहते थे कि समाजवादी पार्टी 2024 में पांच सीट जीत जाए तो बड़ी बात होगी. लेकिन सपा 37 सीट जीत गई. हालांकि 17 सीट लड़ कर कांग्रेस क्यों सिर्फ छह सीट जीत पाई इसका जवाब उनके पास नहीं था. लेकिन वे विधानसभा चुनाव में बराबरी की सीटों का समझौता चाहते हैं. दूसरी ओर तमिलनाडु में कांग्रेस नेताओं ने अलग तैयारी शुरू कर दी है.

1977 में गई सत्ता, 2021 में शून्य पर कांग्रेस

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी करीब पांच महीने बाकी हैं, लेकिन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में 'सियासी महाभारत' का अनौपचारिक ऐलान कर दिया है. प्रधानमंत्री मोदी दो हफ्ते पहले बंगाल बंगाल पहुंचे थे. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो दिन बंगाल में बिताए.

प्रदेश स्तर पर पार्टी पहले से ही सक्रिय है. दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बदतर हालत में पहुंच चुकी कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है. न तो प्रदेश स्तरीय नेता उतने एक्टिव नजर आ रहे हैं और न ही दिल्ली से दबिश दी जा रही है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग से पहले ही राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं. साल 1977 में पश्चिम बंगाल में सत्ता खो देने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी के कोई संकेत नहीं दिखा रही है. केंद्र में सत्ता में लौटने का सपना देखने वाली कांग्रेस पश्चिम बंगाल में व्यावहारिक रूप से गायब हो गई है.

इसके बावजूद भाजपा की तुलना में कांग्रेस की तैयारी बहुत कमजोर स्थिति में है. लंबे समय तक पश्चिम बंगाल पर शासन करने वाली कांग्रेस ने पिछले 10 चुनावों में लगातार खराब प्रदर्शन किया है. लगातार पार्टी का ग्राफ गिरा है और अब शून्य के करीब पहुंच गई है.

2021 में नहीं खुला कांग्रेस का खाता

2021 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही. 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने केवल एक लोकसभा सीट जीती. इसका मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व शून्य की ओर बढ़ रहा है. पार्टी जिस तरह का रवैया दिखा रही है उससे इस बार चुनाव में बी खाता खुल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है. जिसको लेकर पार्टी के अंदर ही नेता दबी आवाज में सवाल उठा रहे हैं.

विशेष भाजपा का टेंशन बढ़ा, कांग्रेस भी 'पवार पावर' से परेशान

फडणवीस के गढ़ में 'अपनों' की बगावत

नागपुर. महाराष्ट्र की उपराजधानी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का होम ग्राउंड इस समय एक बड़ी सियासी अग्निपरीक्षा का केंद्र बना हुआ है.

महानगरपालिका के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है और यहां की सत्ता पर पिछले 15 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार 'जीत का चौका' लगाने की कड़ी चुनौती है. भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल महायुति के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और खुद पार्टी के भीतर से आ रही है. सूत्रों के अनुसार, शिंदे की शिवसेना को गठबंधन में मात्र 8 सीटें मिली हैं जिससे नाराज होकर 30 से अधिक नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है. इसके अलावा भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए अपने 108 मौजूदा पार्षदों में से 63 के टिकट काट दिए हैं जिससे पार्टी के भीतर भी असंतोष की लहर है. भाजपा के चुनाव प्रभारी इन नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं क्योंकि यह बगावत सीधे तौर पर हिंदुत्व वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है.

कांग्रेस और विपक्ष का समीकरण- विपक्ष में कांग्रेस ने सभी 151 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है लेकिन उसकी राह में शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी बाधा बन रही है. शरद पवार की पार्टी ने 76 और अजीत पवार की पार्टी ने 96 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जो कांग्रेस के पारंपरिक दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं. विशेष रूप से प्रभाग 21-डी और वार्ड 13 जैसे क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. कुछ राजनीतिकों का मानना है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है. भले ही कुछ सीटों पर बागी प्रत्याशी हो किंतु मतदाता निश्चित ही समझदार हो गया है.

> **साख की लड़ाई**
>
> मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो 1997 में मात्र 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बने थे, उनके लिए यह चुनाव अपनी राजनीतिक विरासत और गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है. 151 सीटों वाले इस सदन में भाजपा ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि राज ठाकरे की मनसे ने भी 22 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. यह चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों का नहीं बल्कि आने वाले बड़े चुनावों के लिए एक लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है. भारी संख्या में बागी प्रत्याशियों के उतरने की भनक लगते ही अब स्वयं फडणवीस ने कुछ हद तक बागडोर अपने हाथों में ले ली है जिससे नामांकन वापसी तक कुछ प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं.